



विनिर्माण क्षेत्र के बल पर भारत की प्रगति: निष्पादन और नीति

वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व के लिए सुधार, लचीलापन और रोडमैप

19 सितंबर, 2025

मुख्य बातें

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जुलाई में 3.5 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़ गया, जो -5.4 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष विनिर्माण वृद्धि से प्रेरित है।
- पीएलआई, पीएम मित्र, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और स्किल इंडिया जैसी प्रमुख योजनाएं क्षमता निर्माण में तेजी ला रही हैं और भारत के विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत कर रही हैं।
- अप्रैल-अगस्त 2025 में मर्चेडाइज निर्यात 2.52 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष बढ़कर 184.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने से, भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इंजन मजबूत बना रहा।
- अगस्त 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर (यूआर) 5 महीने के निचले स्तर से 5.0 प्रतिशत तक कम हो गई है।

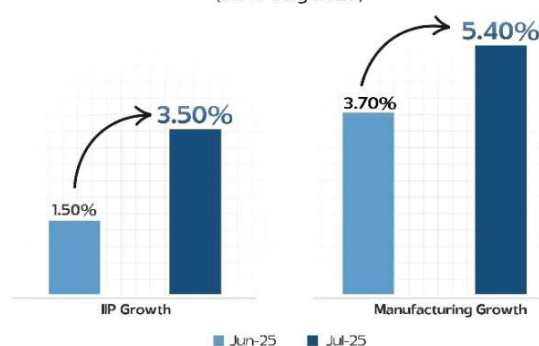
एक महत्वपूर्ण मोड़ पर विनिर्माण

हर बड़ी अर्थव्यवस्था के मूल में कारखानों की एक कहानी होती है और भारत के लिए, यह कहानी तेजी से सामने आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में, विनिर्माण क्षेत्र देश के विकास मॉडल का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरा है, जिसने न केवल घरेलू मांग को पूरा किया है, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को भी मजबूत किया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) विनिर्माण, खनन और बिजली के क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा को ट्रैक करता है। यह इस

Measuring the Momentum IIP & Manufacturing Growth

(June-July 2025)

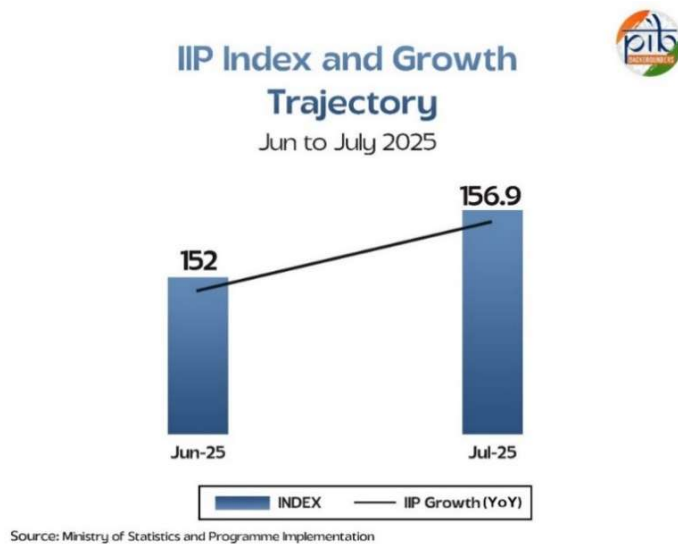


बात का एक स्नेपशॉट है कि उद्योग कैसा प्रदर्शन कर रहा है और जीडीपी वृद्धि में इसका कैसा योगदान है। जुलाई 2025 में, आईआईपी ने वर्ष-दर-वर्ष 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो जून 2025 में 1.5 प्रतिशत से काफी बढ़ रही है। **जुलाई 2025 में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी साल-दर-साल 5.40 प्रतिशत बढ़ गई, जो जून 2025 के 3.7 प्रतिशत से अधिक है।**

भारत की विकास गाथा आधुनिक कल-कारखाने के सक्रिय संचालन से तेजी से आगे बढ़ रही है। पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) से लेकर चेन्नई में **लैपटॉप असेंबली लाइन तक**, यह सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि के प्रसार को दर्शाता है। पर्दे के पीछे, पीएलआई, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और अन्य जैसी नीतियां इन केंद्रों को उच्च-प्रदर्शन वाले नोड्स में बदल रही हैं।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव और भारत के घरेलू बाजार के विस्तार के साथ, यह क्षेत्र समग्र विकास को आगे बढ़ाते हुए उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

निष्पादन में तेजी



जुलाई, 2025 में आईआईपी में वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण द्वारा संचालित थी, जो बढ़ती मांग और उद्योगों में मजबूत क्षमता के इस्तेमाल को दर्शाती है।

आईआईपी उछाल को कौन बढ़ावा दे रहा है?

विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, 23 उद्योग समूहों में से, 14 ने जुलाई 2025 में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। अग्रणी कलाकारों में शामिल हैं:

- बुनियादी धातु: (12.7प्रतिशत)
- विद्युत उपकरण: (15.9प्रतिशत)
- अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद: (9.5प्रतिशत)

यह गति एचएसबीसी इंडिया मैनुफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) में भी दिखाई देती है। जून 2025 में, पीएमआई 58.4 पर था, जो अगस्त में 59.3 तक पहुंचने से पहले जुलाई में 59.1 तक चढ़ गया। यह 16 महीनों में सबसे अधिक है। इस नवीनतम रीडिंग ने 17 वर्षों में संचालन की स्थितियों में सबसे तेजी से सुधार का संकेत दिया।

यह वृद्धि उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि से प्रेरित थी, जो नए कारखाने के ऑर्डर में मजबूत वृद्धि के साथ-साथ लगभग पांच वर्षों में सबसे तेज वृद्धि थी। कंपनियों ने इनपुट खरीद को बढ़ाकर और अपने कार्यबल का विस्तार करके जवाब दिया, जिससे क्षेत्र की निकट अवधि की संभावनाओं में विश्वास को दर्शाया गया।

आईआईपी की वृद्धि भारत की व्यापक औद्योगिक महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। 2047 तक आजादी के अमृत काल में हमारा लक्ष्य सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग में लीडरशिप, लाखों रोजगार पैदा करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है।

कुल मिलाकर, ये संकेतक एक स्पष्ट और तीव्र वृद्धि दिखाते हैं: भारत अपने आर्थिक विकास की नींव रख रहा है, जिसके मूल में विनिर्माण है।

विकास के इंजन: आगे बढ़ रहे क्षेत्र

भारत का विनिर्माण निर्यात इंजन चहुमुखी काम कर रहा है क्योंकि व्यापक तौर पर व्यापार में स्थायित्व आ रहा है।

निर्यात में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्पष्ट है। अप्रैल-अगस्त 2025 में, कुल निर्यात 6.18 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 349.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान व्यापारिक निर्यात का कुल मूल्य 184.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान यह 179.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 2.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

विनिर्माण क्षेत्र में दिखाई देने वाले विकास के साथ, यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 26 में 87,57,000 करोड़ रुपये (1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने की क्षमता है और संभावित रूप से 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सालाना 43,43,500 करोड़ रुपये (500 बिलियन अमेरिकी) से अधिक जुड़ सकता है, जो इंगित करता है कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है।

जबकि जुलाई की आईआईपी वृद्धि मुख्य रूप से **बुनियादी धातुओं, विद्युत उपकरणों और गैर-धातु खनिजों** द्वारा संचालित थी, भारत के विनिर्माण उत्थान की व्यापक कहानी इन श्रेणियों से परे है। इन उच्च प्रदर्शन वाले उद्योगों के साथ-साथ, **रणनीतिक क्षेत्रों-इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल** का एक समूह दीर्घकालिक संरचनात्मक विकास को बढ़ावा दे रहा है और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को आकार दे रहा है।

साथ में, ये क्षेत्र न केवल भारत की निर्यात गति को मजबूत करते हैं बल्कि **वित्त वर्ष 2026 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विनिर्माण अर्थव्यवस्था** बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी मजबूत करते हैं। निम्नलिखित विवरण यह दर्शाते हैं कि कैसे ये उद्योग भारत के विनिर्माण क्षेत्र में पुनर्जागरण के इंजन के रूप में उभर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स: भारत का कारखाना संचालन डिजिटल हो गया

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में **पिछले 11 वर्षों** में उत्पादन में छह गुना वृद्धि और निर्यात में **आठ गुना वृद्धि देखी गई है**। वित्त वर्ष 2027 तक 90 प्रतिशत तक पहुंचने के लक्ष्य से प्रेरित इलेक्ट्रॉनिक्स **वैल्यू एडिशन 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ गया है**।

#	2014-15	2024-25	टिप्पणी
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	1.9 लाख करोड़	11.3 लाख करोड़	6 गुना से अधिक वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (रु.)	38 हजार करोड़	3.27 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल विनिर्माण इकाइयां	2	300	150 गुना वृद्धि
मोबाइल फ़ोन का उत्पादन (रु.)	18 हजार करोड़	5.45 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फ़ोन का निर्यात (रु.)	1,500 करोड़	2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि
आयातित मोबाइल फ़ोन (इकाइयां)	कुल मांग का 75 प्रतिशत	कुल मांग का 0.02 प्रतिशत	

मोबाइल विनिर्माण सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक रहा है। एक दशक पहले सिर्फ दो इकाइयों से बढ़कर, भारत में अब लगभग 300 इकाइयां हैं, जो उत्पादन क्षमता में 150 गुना विस्तार को दर्शाती हैं। मोबाइल फोन का निर्यात और भी बेजोड़ कहानी कहता है। यह मामूली 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 127 गुना अधिक है। साथ ही, आयात पर निर्भरता 2014-15 में आयात के माध्यम से पूरी की जा रही घरेलू मांग के 75 प्रतिशत से लगभग गायब होकर 2024-25 में केवल 0.02 प्रतिशत रह गई है। कुल मिलाकर, ये आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक केंद्र बनने के लिए एक बड़े आयातक से भारत के बदलाव को दर्शाते हैं। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है।

भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 4 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक एफडीआई प्रवाह को आकर्षित किया है और इस एफडीआई का लगभग 70 प्रतिशत पीएलआई योजना के लाभार्थियों द्वारा योगदान दिया गया है।

फार्मा उद्योग: "विश्व की फार्मसी"

भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग एक वैश्विक पावरहाउस है। यह उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है और उत्पादन मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर है, जो वैश्विक वैक्सीन मांग का 50 प्रतिशत से अधिक और अमेरिका को लगभग 40 प्रतिशत जेनेरिक की आपूर्ति करता है। उद्योग के 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार तक बढ़ने का अनुमान है।

फार्मास्यूटिकल्स के लिए नीतिगत समर्थन जैसे पीएलआई योजना (15,000 करोड़ रुपये) और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग (एसपीआई) योजना (500 करोड़ रुपये) को मजबूत करने के साथ, उद्योग अपनी वैश्विक उपस्थिति का निरंतर विस्तार कर रहा है। पीएलआई योजना भारत में कैंसर और मधुमेह की दवाओं जैसी अत्याधुनिक दवाओं को बनाने के लिए 55 परियोजनाओं में निवेश कर रही है, जबकि एसपीआई योजना जो छोटी फार्मा कंपनियों की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलेपन को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण कर रही है, जिससे भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो रही हैं। लागत दक्षता से परे, भारत सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के केंद्र के रूप में उभरा है, जो "विश्व की फार्मसी" के रूप में अपने सही दर्जे को मजबूत करता है।

ऑटोमोबाइल: तीव्र बदलाव की ओर

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का मोटर वाहन उद्योग देश के विनिर्माण और आर्थिक विकास की आधारशिला है, जो **भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.1 प्रतिशत और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 49 प्रतिशत** का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों, तीन-पहिया, दोपहिया और क्वाड्रिसाइकिल का कुल

उत्पादन 3.10 करोड़ यूनिट से अधिक था। **विश्व स्तर पर चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक** के रूप में, भारत के पास ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरने के लिए व्यापकता और रणनीतिक गहराई है।



वस्त्र उद्योग: उभरता नेतृत्व

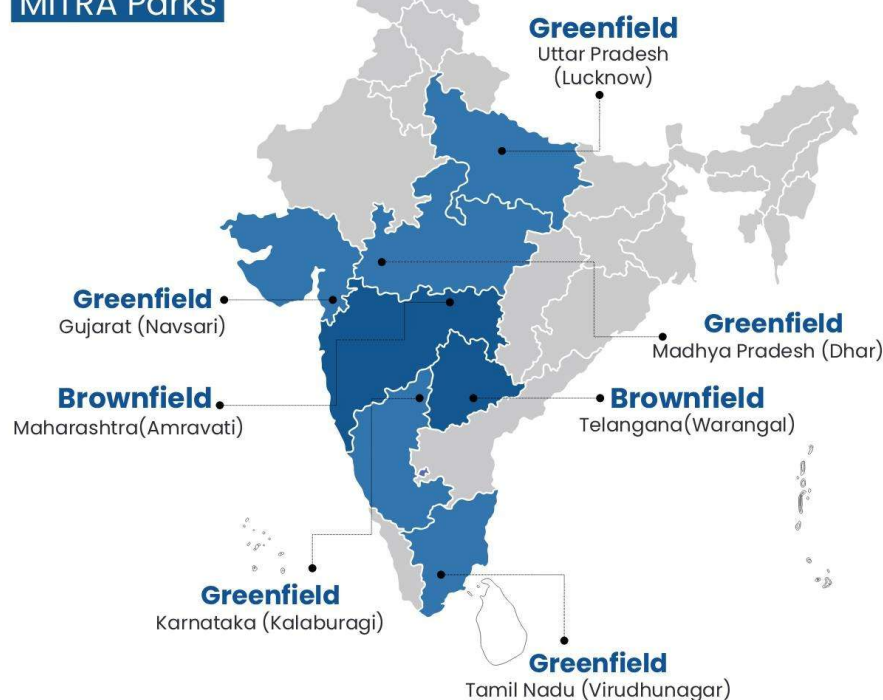
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, भारत का कपड़ा और परिधान उद्योग विश्व स्तर पर सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जो **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.3 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 13 प्रतिशत और कुल निर्यात में 12 प्रतिशत** का योगदान देता है।

यह क्षेत्र 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने के लिए तैयार है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। इस वृद्धि से **3.5 करोड़ रोजगार** सृजन होने की उम्मीद है। यह **कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक भी है**। इसमें **45 मिलियन से अधिक लोग** सीधे रोजगार प्राप्त करते हैं, जिनमें **महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं**। इस उद्योग की समावेशी प्रकृति के और प्रमाण के रूप में, इसकी क्षमता का लगभग **80 प्रतिशत देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) समूहों में फैला हुआ है**।

उद्योग को और अधिक समर्थन देने के लिए, सरकार ने 2027-28 तक छह वर्षों में **4,445 करोड़ रुपये** के समर्थन से **सात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्कों** को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, पार्कों का लक्ष्य **70,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना**

है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया, जहां 1,300 एकड़ भूमि और 80 से अधिक औद्योगिक इकाइयां आवंटित की गई हैं। इस पार्क से करीब **तीन लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।**

THE SEVEN PM MITRA Parks



Source: Ministry of Textiles

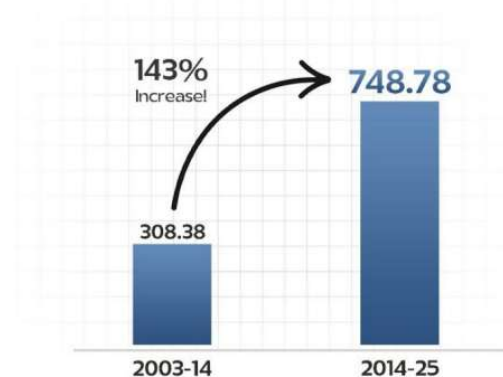
निवेश प्रवाह और वैश्विक विश्वास

भारत ने वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को लगातार स्थापित किया है। पिछले एक दशक में, लगातार सुधारों, सरल नियमों और एक स्थिर नीति वातावरण ने विनिर्माण में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है। लक्षित क्षेत्रीय प्रोत्साहनों के साथ कारोबारी सुगमता को बढ़ाने की पहल ने वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया है।

- पिछले 11 वर्षों (2014-25) में भारत में कुल एफडीआई प्रवाह **748.78 बिलियन अमरीकी डालर** था, जो **2003-14 के दौरान प्राप्त 308.38 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 143 प्रतिशत अधिक** था।
- भारत ने **वित्त वर्ष 2024-25 में सकल एफडीआई प्रवाह में 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रदर्शन किया , जो साल-दर-साल 14 प्रतिशत की वृद्धि है।**
- वित्त वर्ष 2024-25 में **विनिर्माण एफडीआई 18 प्रतिशत बढ़कर 19.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया** (वित्त वर्ष 2023-24 में 16.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से)
- **महाराष्ट्र ने 39 प्रतिशत इक्विटी प्रवाह के साथ एफडीआई लीडरबोर्ड का नेतृत्व किया, इसके बाद 2024-25 में कर्नाटक (13 प्रतिशत) और दिल्ली (12 प्रतिशत) का स्थान रहा।**
- **सिंगापुर (30 प्रतिशत) मॉरीशस (17 प्रतिशत) और संयुक्त राज्य अमेरिका (11 प्रतिशत) से आगे शीर्ष पर बना रहा, जो पूंजी-बाजार मध्यस्थता और रणनीतिक निवेशकों दोनों को दर्शाता है जो अपने भारत की उपस्थिति को मजबूत कर रहा है।**
- सरकार का लक्ष्य **वार्षिक एफडीआई प्रवाह को 100 बिलियन अमरीकी डालर तक**

FDI Inflows into India

(In USD Billion)



Source: Ministry of Commerce & Industry

बढ़ाना है।

ये रुझान एक पसंदीदा वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हैं, जो एक सकारात्मक नीतिगत ढांचे, एक विकसित व्यापारिक इको-सिस्टम और भारत के आर्थिक सशक्तता में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास द्वारा सक्षम है।

रोजगार, कौशल और मानव पूंजी

विनिर्माण केवल मशीनों और असेंबली लाइनों के बारे में नहीं है, बल्कि यह लोगों के बारे में भी है। रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में, विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों के लिए भारत के रोजगार बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

पिछले एक दशक में 17 करोड़ रोजगार के सृजन के साथ भारत के रोजगार में वृद्धि हुई है, जो युवा-केंद्रित नीतियों पर सरकार के फोकस और उसके विकसित भारत दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगस्त 2025 के हालिया पीएलएफएस डेटा इस सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) बढ़कर 52.2 प्रतिशत हो गया, जबकि महिला डब्ल्यूपीआर 32 प्रतिशत तक चढ़ गया, जो महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में स्थिर लाभ को दर्शाता है। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भी इस साल लगातार दूसरे महीने सुधार हुआ, जो महिलाओं के लिए 33.7 प्रतिशत तक पहुंच गया। अगस्त 2025 में पुरुषों के बीच समग्र बेरोजगारी दर घटकर 5.1 प्रतिशत हो गई और पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर (यूआर) 5 महीने के निचले स्तर से घटकर 5.0 प्रतिशत हो गई, जो विनिर्माण सहित सभी क्षेत्रों में व्यापक रोजगार सृजन और समावेशिता को उजागर करती है। विनिर्माण क्षेत्र में, रोजगार सृजन 2004 और 2014 के बीच 6 प्रतिशत था, जबकि पिछले दशक में यह बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया।

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के विनिर्माण इको-सिस्टम को एक मजबूत और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। एक प्रमुख प्रवर्तक स्किल इंडिया कार्यक्रम का पुनर्गठन है, जिसका परिचय 8,800 करोड़ (1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जिसे 2026 तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना को एक एकीकृत, उद्योग-अनुकूल संरचना में एकीकृत करके, यह पहल आधुनिक उद्योग की उभरती जरूरतों के अनुरूप एक मांग-प्रेरित, प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यबल का निर्माण कर रही है।



कुल मिलाकर, इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को एक प्रतिस्पर्धी, कुशल और अनुकूली कार्यबल के निर्माण में प्रभावी ढंग से लगाया जाए जो मानव पूंजी को औद्योगिक विकास के सच्चे इंजन में बदल दे।

नीतिगत उत्प्रेरक के बल पर बदलाव

इस आधार पर, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास, शहरी विकास और उद्यमिता में फैले पूरक नीतिगत उपायों का एक सेट भारत में विनिर्माण क्षेत्र के बदलाव के अगले चरण को आकार दे रहा है। प्रमुख पहलों ने निवेश, नवाचार और पैमाने के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम बनाया है, जिससे औद्योगिक जीवंतता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। हाल ही में घोषित **जीएसटी 2.0 सुधारों** ने दो-स्लैब संरचना को सरल बनाने और आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कमी के साथ अनुपालन लागत को कम किया है और खपत को बढ़ावा दिया है।

कुल मिलाकर, ये उपाय न केवल भारत के घरेलू विनिर्माण आधार को मजबूत कर रहे हैं बल्कि देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रतिस्पर्धी दिग्गज के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं।

जीएसटी 2.0

जिस तरह कारखाने स्थिर मांग और कम लागत पर फलते-फूलते हैं, उसी तरह भारत की हालिया जीएसटी दर में कटौती ईंधन के रूप में आती है जो विनिर्माण को संचालित रखता है। इससे घरों के लिए सामान सस्ता हो जाता है, उद्योगों के लिए इनपुट हल्का हो जाता है और अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है।

प्रमुख औद्योगिक लाभों में शामिल हैं:

- **लागत कम और मजबूत मूल्य श्रृंखलाएं:** पैकेजिंग, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और आवश्यक रसद वस्तुओं जैसे सामानों पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिससे विनिर्माण लागत में कटौती होती है और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है
- **एमएसएमई और निर्यातोन्मुखी उद्योग सशक्त:** कपड़ा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, खिलौने और चमड़ा उद्योगों में तर्कसंगत दरें और तेजी से रिफंड कार्यशील पूंजी की बाधाओं को कम करता है और बड़े पैमाने पर समर्थन करता है
- **लॉजिस्टिक्स पर कम लागत:** ट्रकों और डिलीवरी वैन पर जीएसटी (28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक) कम पैकेजिंग लागत के साथ संयुक्त रूप से आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को मजबूत करता है और माल ढुलाई से जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा
- **व्यापार करने में आसानी और अनुपालन:** छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए पंजीकरण नियमों में ढील जैसे प्रक्रियात्मक सरलीकरण के साथ सरल स्लैब संरचना नियामक घर्षण को कम करेगी और औपचारिक भागीदारी को बढ़ावा देगी
- **ऑटो और समर्थक इको-सिस्टम में तेजी:** वाहनों (350सीसी तक के दोपहिया वाहनों सहित), ऑटो पार्ट्स और ट्रेक्टरों पर जीएसटी में कटौती उपभोक्ता सामर्थ्य और ईंधन की मांग को बढ़ाएगी और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: रणनीतिक दिशा

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम), भारत की औद्योगिक नीति का मुकुट रत्न है। यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप है जो नीति, निष्पादन और शासन को एकल, एकीकृत दृष्टि में एकीकृत करता है। पिछले खंडित दृष्टिकोणों के विपरीत, एनएमएम को एक मिशन-मोड ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है जो एक सिंक्रनाइज्ड विनिर्माण पुश बनाने के लिए मंत्रालयों और राज्यों में कटौती करता है।



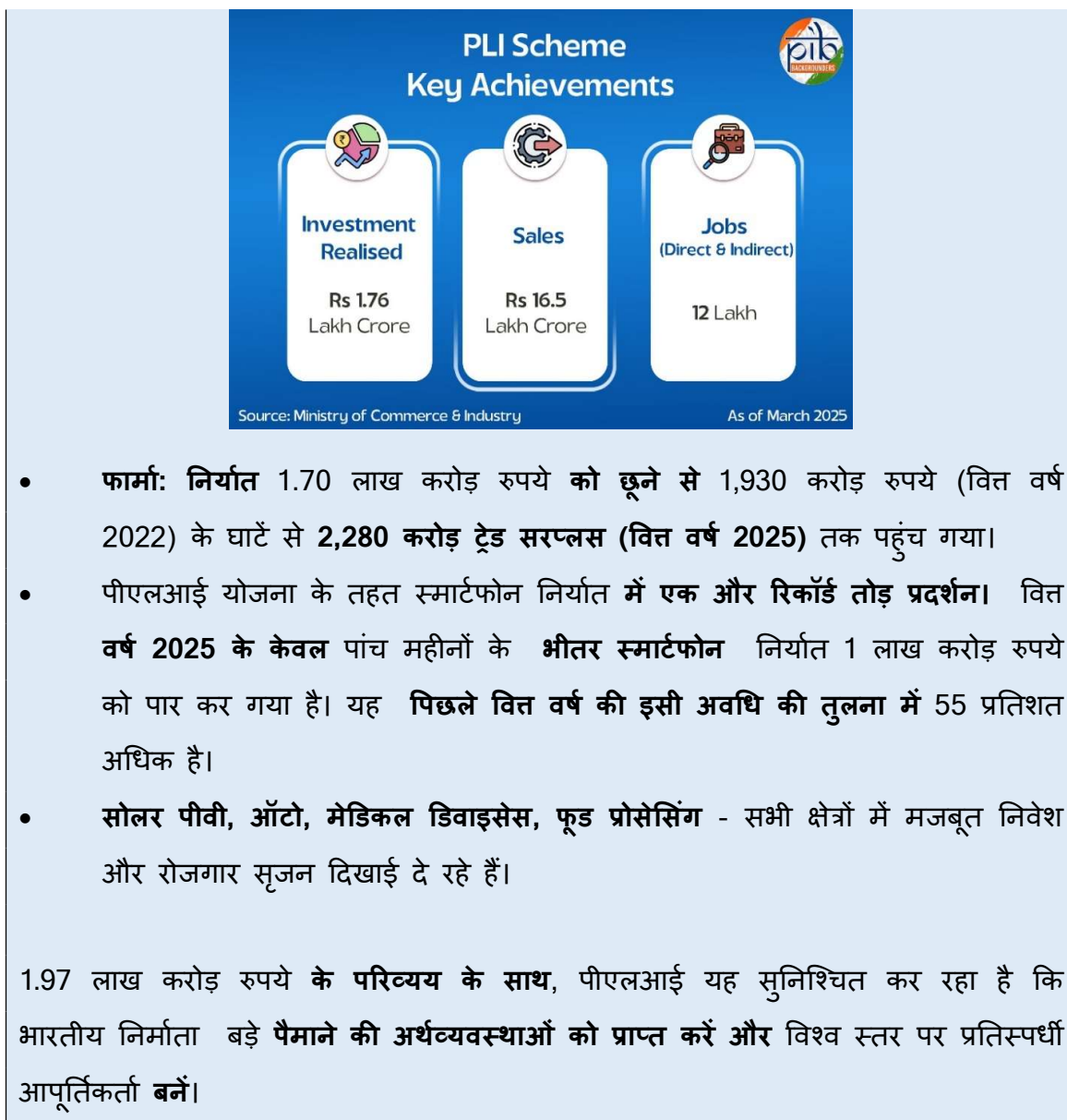
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एनएमएम स्थायित्व को औद्योगीकरण के केंद्र में रखता है। यह सौर पीवी मॉड्यूल और ईवी बैटरी से लेकर हरित हाइड्रोजन और पवन टर्बाइनों तक स्वच्छ-तकनीक विनिर्माण को प्राथमिकता देता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत का उदय इसकी नेट-जीरो 2070 के संकल्प के अनुरूप हैं।

संक्षेप में, एनएमएम केवल एक नीति नहीं है, यह विश्व मंच पर वृद्धिशील लाभ से विनिर्माण की अगुवाई में भारत के परिवर्तन का मार्गदर्शन करने वाला रणनीतिक कम्पास है।

पीएलआई योजना: व्यापकता, गति, रोजगार

2020 में शुरू की गई प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र से लेकर ड्रोन तक के 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली यह योजना वृद्धिशील उत्पादन और बिक्री से सीधे जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

कुछ असाधारण परिणामों में शामिल हैं:



राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य लागत कम करके, दक्षता बढ़ाकर और डिजिटल एकीकरण को चलाकर भारत के लॉजिस्टिक्स इको-सिस्टम को ओवरहाल करना है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ मिलकर काम करते हुए, एनएलपी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है: लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) में भारत की स्थिति को शीर्ष 25 देशों में सुधारना और एक मजबूत, डेटा-संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली का निर्माण करना। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने डिजिटल सिस्टम, मानकीकरण, मानव संसाधन विकास, राज्य-स्तरीय समन्वय और लॉजिस्टिक्स पार्कों के निर्माण पर ध्यान

केंद्रित करते हुए व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान (सीएलएपी) शुरू किया है। साथ में, इन पहलों को निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।

स्टार्ट-अप इंडिया

16 जनवरी, 2016 को शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने उद्यमियों का समर्थन करने, एक मजबूत स्टार्टअप इको-सिस्टम का निर्माण करने और भारत को रोजगार चाहने वालों के बजाय रोजगार प्रदाताओं के देश में बदलने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत 9 सितंबर 2025 तक 1.91 लाख डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम का दावा करता है, जिसने 31 जनवरी, 2025 तक 17.69 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। यह उल्लेखनीय वृद्धि नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में पहल की सफलता को दर्शाती है।

औद्योगीकरण और शहरीकरण

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत की सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है। इसका उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को "स्मार्ट सिटी" के रूप में बनाना है। यह कार्यक्रम मजबूत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के साथ एकीकृत औद्योगिक गलियारों को विकसित करने, विनिर्माण और व्यवस्थित शहरीकरण में विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पिछले साल, सरकार ने 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें अनुमानित 28,602 करोड़ रुपये का निवेश शामिल था। यह इस परिवर्तनकारी प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को विनिर्माण और निवेश के लिए एक अग्रणी वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करता है।

आगे का रास्ता: गति से नेतृत्व तक

जैसे-जैसे भारत 2047 तक अपने 35 ट्रिलियन डॉलर के विजन की ओर आगे बढ़ रहा है, विनिर्माण ही विकास का इंजन साबित होने वाला है। सुधारों, क्षेत्रीय प्रोत्साहनों और सशक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं द्वारा समर्थित, इस क्षेत्र ने तेज गति प्राप्त की है, जो फिच रेटिंग, आईएमएफ और एसएंडपी ग्लोबल आउटलुक में संशोधित जीडीपी विकास अनुमानों और विनिर्माण पीएमआई (एसएंडपी ग्लोबल) में 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने में परिलक्षित होता है। इस क्षेत्र ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी मजबूती दिखाई है।

पीएलआई योजना, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और कौशल विकास पहल जैसी परिवर्तनकारी नीतियों द्वारा समर्थित सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने का सरकार का दृष्टिकोण, औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के रणनीतिक पुनर्गठन के दौर से गुजरने के साथ, भारत के पास निवेश, नवाचार और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में आगे बढ़ने का अवसर है। यदि इस गति को बनाए रखा जाता है, तो भारत "दुनिया का कारखाना" से "दुनिया का नवाचार और नेतृत्व केंद्र" के रूप में बदल सकता है।

इस्तेमाल किए गए संदर्भ:

नीति आयोग

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2121826>
- https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-06/Automotiveप्रतिशत20Industryप्रतिशत20Poweringप्रतिशत20Indiaप्रतिशतE2प्रतिशत80प्रतिशत99sप्रतिशत20participationप्रतिशत20inप्रतिशत20GVC_Nonप्रतिशत20Confidential.pdf

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc2025828622401.pdf>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149266>
- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/may/doc2025530560501.pdf>

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152196>

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117470>

- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseFramePage.aspx?PRID=1957407>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2050136>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2166813>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2131716>

स्टार्टअप इंडिया

- <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startup-scheme.html>

स्किल इंडिया

- <https://www.skillindiadigital.gov.in/pmkvy-dashboard>
- <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/>

वित्त मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098392>
- <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

वस्त्र मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115710>
- https://samarth-textiles.gov.in/public_dashboard/dashboard/data

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/sites/default/files/file-uploads/sciencetechnologypolicies/1527506858_po-ann3.pdf

श्रम और रोजगार मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1907686>

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1872289>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099656>

संसदीय प्रश्न

- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2950_wssjkG.pdf?source=pqals

- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4365_n5AXht.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1950_otUvW.pdf?source=pqals

पत्र सूचना कार्यालय

- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/jan/doc202516481901.pdf>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152038&ModuleId=3>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155082&ModuleId=3>
- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc2025818614701.pdf>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154840&ModuleId=3>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2167537>

डीडी न्यूज

- <https://ddnews.gov.in/en/indias-manufacturing-pmi-rises-to-16-month-high-in-july-despite-global-uncertainties/>

सीआईआई

- [https://www.cii.in/International_ResearchPDF/Achievingप्रतिशत20USD1प्रतिशत20Trillionप्रतिशत20Merchandiseप्रतिशत20Exportsप्रतिशत20byप्रतिशत202030प्रतिशत20-प्रतिशत20Aप्रतिशत20Roadmapप्रतिशत20\(1\).pdf](https://www.cii.in/International_ResearchPDF/Achievingप्रतिशत20USD1प्रतिशत20Trillionप्रतिशत20Merchandiseप्रतिशत20Exportsप्रतिशत20byप्रतिशत202030प्रतिशत20-प्रतिशत20Aप्रतिशत20Roadmapप्रतिशत20(1).pdf)

एसएंडपी ग्लोबल

- <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9806df5729e64068a9d3c6e17c8ee67b>

एक्स

- https://x.com/AshwiniVaishnaw/status/1967496528135889375?t=V_V2J06uLWJcKc8COoFV4g&s=08

पीके/केसी/एसकेएस/एसवी

